# बजट ₹ उम्मीदें 2015 शिक्षा

**3.17** फीसदी हिस्सा कुल घरेलू उत्पादन का खर्च होता है शिक्षा पर, जो 4.3 के वैश्विक औसत से कम है.

**शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति के बावजूद भारत के लाखों बच्चे आज भी स्कूल नहीं जा पाते हैं. महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों से निकल रहे स्नातकों में बड़ी संख्या ऐसी है, जो रोजगार के लिए सक्षम नहीं है. तकनीकी और पेशेवर शिक्षा के इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार के अवसरों की कमी के कारण नौजवान कौशल-प्रशिक्षण से वंचित है. देश को आगामी बजट से कई आशाएं और अपेक्षाएं हैं. शिक्षा से जुड़ी उम्मीदों पर एक परिचर्चा प्रस्तुत है आज के विशेष में**

## शिक्षा की स्थिति

**6.9** फीसदी हिस्सा घरेलू बजट का औसतन खर्च करता है शिक्षा पर एक भारतीय परिवार.

**68,728** करोड़ रुपये आवंटित किये गये थे शिक्षा क्षेत्र को 2014-15 के बजट में.

**51,828** करोड़ आवंटित किये गये थे विद्यालय क्षेत्र को पिछले बजट में.

**16,900** करोड़ रुपये प्रस्तावित किये गये थे उच्च शिक्षा को 2014-15 के बजट में.

**7,138.97** करोड़ रुपये उच्च शिक्षा के बजट से आइआइटी और आइआइएम संस्थानों को दिये गये थे.

**28,635** करोड़ रुपये विद्यालय आवंटन में से सर्व शिक्षा अभियान के लिए दिये गये थे.

**160** बिलियन डॉलर का अनुमानित मूल्यांकन है देश के समूचे शिक्षा क्षेत्र का.

**02** फीसदी से भी कम भारतीय आबादी के पास औपचारिक रूप से कौशल-प्रशिक्षण है.

**50** करोड़ भारतीय निवासियों को कौशल-प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है वर्ष 2022 तक.

**2.32** खरब रुपयों के निवेश की आवश्यकता होगी सरकारी स्कूलों को निजी स्कूलों की उत्कृष्टता के स्तर तक लाने के लिए.

**45** हजार रुपये गोवा में वार्षिक खर्च होता है सरकारी स्कूल में पढ़ रहे औसतन एक बच्चे पर, जबकि बिहार में यह खर्च सबसे कम महज 4,300 रुपये ही है.

स्रोत : भारत सरकार, एनएसएसओ और असर रिपोर्ट की सूचनाएं

## शिक्षण की गुणवत्ता के साथ बदलना होगा

# शिक्षा का स्वरूप

मनीष सभरवाल
**चेयरमैन, टीमलीज**

**उम्मीद है कि इस बजट में शिक्षा को लेकर बड़ी घोषणाएं होगी और सरकार रोजगारपरक शिक्षा व्यवस्था बनाने की दिशा में कदम उठायेगी. संस्थानों के निर्माण के अलावा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराने के लिए केंद्र सरकार कदम उठायेगी. सबसे अधिक कॉलेज होने के बावजूद अगर भारत कुशल कामगार नहीं मुहैया करा पा रहा है, तो यह हमारे शिक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी कमी मानी जा सकती है.**

देश की शिक्षा व्यवस्था के सामने कई चुनौतियां हैं. स्कूलों में नामांकन दर बढ़ाने के लिए सरकार ने शिक्षा का अधिकार कानून बनाया. इस कानून के लागू होने के बाद स्कूलों में नामांकन दर काफी बढ़ गया, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार नहीं हुआ. अब समय आ गया है कि सरकार शिक्षा के अधिकार से आगे बढ़ते हुए सीखने के अधिकार पर ध्यान केंद्रित करे. नामांकन की जंग देश ने जीत ली है, अब शिक्षण की गुणवत्ता की ओर जाना होगा. शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने के बाद नामांकन दर बढ़ाने, स्कूलों में सुविधा और भवन निर्माण पर फोकस किया गया. अब इस सोच को बदलते हुए शिक्षकों की ट्रेनिंग, तकनीक का प्रयोग और वोकेशनल शिक्षा पर जोर देना होगा.

शिक्षकों की ट्रेनिंग का तरीका काफी पुराना है. शिक्षकों को नये तरीके से छात्रों को सिखाने की ट्रेनिंग देनी चाहिए. शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नये तरीकों पर भी गौर करने की आवश्यकता है. लेकिन देश में बेरोजगारों की संख्या काफी है. भारत में रोजगार निर्माण की स्थिति पिछले 20 सालों से एक जैसी है. रोजगार के मौके बढ़ाने के लिए सरकार ने कुछ महीने पहले एप्रेंटिस एक्ट में बदलाव किया. आज जर्मनी में 30 लाख, चीन में 2 करोड़ और भारत में सिर्फ तीन लाख छात्र इस कोर्स को कर रहे हैं. सरकार को अगले पांच साल में इसे 50 लाख तक करने का लक्ष्य रखना चाहिए. हम इसलिए आगे नहीं बढ़ पाये, क्योंकि हमारी क्या जरूरत है और हम क्या सीख रहे हैं, इसमें काफी अंतर रहा है.

भारत के पास अनूठा मौका है, क्योंकि 65 फीसदी कामगार 35 साल के हैं. चीन इस मामले में पिछड़ रहा है, क्योंकि कृषि के लिए उसके पास कामगार नहीं हैं और वहां मजूदरी की दर तेजी से बढ़ी है. विकसित देशों की अपनी समस्याएं हैं. विकसित देशों की वैश्विक आबादी में हिस्सेदारी 7 फीसदी, जीडीपी में 25 फीसदी और सामाजिक क्षेत्र में खर्च की हिस्सेदारी 50 फीसदी है. ऐसे में अगले 20 साल भारत के लिए सुनहरा मौका है और कुशल युवा भारत को संपन्न बना सकते हैं. लेकिन इसके लिए नीति-निर्माण के केंद्र में रोजगार सृजन होना चाहिए. क्योंकि रोजगार से लोगों का जीवन स्तर बदल जाता है, जो काम सब्सिडी नहीं कर सकता है.

भारत में बड़े पैमाने पर संगठित, गैर- कृषि और निजी क्षेत्र में नौकरी के सृजन करने की जरूरत है. हमें यह समझना होगा कि भारत पूंजी का बाजार है, लेकिन



यह लेबर बाजार नहीं बन पाया है. ऐसे में डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा उठाने के लिए नीतियां उसी अनुरूप बनानी होगी. अगले 20 साल तक भारत के कामगार वर्ग में 10 लाख लोग हर महीने शामिल हो रहे हैं. साथ ही 30 करोड़ कम उत्पादकता के क्षेत्र में लगे लोगों के लिए भी सोचना होगा. इतनी बड़ी आबादी खासकर युवा आबादी तभी देश के काम आयेगी, जब लोग उत्पादक बनें और यह उत्पादकता नौकरी से संबंधित होनी चाहिए. देश में उद्यमिता का माहौल नहीं है. सरकार की नीतियां भी इसमें बाधक हैं. भारत में छोटे-मोट उद्योग-धंधों की संख्या करीब 6.3 करोड़ है, लेकिन कंपनियों की संख्या केवल 9 लाख है. इनमें से महज 45 हजार कंपनियों में ही रोजाना कम से एक नौकरी के अवसर पैदा हो रहे हैं. देश में महज 7,500 कंपनियों की पूंजी 10 करोड़ रुपये से अधिक है. इतनी बड़ी खामी के कारण कंपनियां पूरी क्षमता से विकास नहीं कर पा रही हैं.

रोजगार के सबसे बड़े क्षेत्र मैन्युफैक्चरिंग में 84 फीसदी काम वैसी कंपनियां कर रही हैं, जहां 50 से कम लोग कार्यरत हैं. मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में कुल कामगार के 12 फीसदी कार्यरत हैं, जो अमेरिका में औद्योगिक क्रांति के पहले जैसी स्थिति है. आज भी देश में 50 फीसदी से अधिक लोग कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं, यानी देश का आधा कामगार जीडीपी में 15 फीसदी की भागीदारी दे रहा है. चीन विश्व का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया, क्योंकि वहां विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर, विदेशी निवेश और कुशल कामगार कम कीमत पर उपलब्ध हैं. लेकिन पिछले 10 सालों में मजदूरी बढ़ी और इसका फायदा वियतनाम उठा रहा है. ऐसे में सरकार को स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने पर जोर देने की बजाय हमें कानून सम्मत व्यवस्था बनाने, लघु, मध्यम और छोटे उद्योग मंत्रालय की कार्यप्रणाली में बदलाव लाना होगा. साथ ही श्रम और इंस्पेक्टर राज व्यवस्था को खत्म करना होगा.

### विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था जरूरी

रोजगार बढ़ाने के लिए शहरीकरण की रफ्तार बढ़ानी होगी. दिल्ली, मुंबई, बंगलुरू जैसे शहरों में रोजगार के मौके बढ़ाने से काम नहीं चलेगा. इसके लिए हमें 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों को विकसित करना होगा. शहरीकरण का मतलब विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था बनाना भी है. शहरीकरण के लिए 29 राज्यों के मुख्यमंत्री देश के प्रधानमंत्री से अधिक महत्वपूर्ण हैं. व्यक्ति विशेष की उत्पादकता शिक्षा और कौशल पर निर्भर करती है. स्कूल, वोकेशनल और उच्च शिक्षा के बीच तारतम्य होना चाहिए. नीति-निर्माताओं ने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया. आज देश में डिग्रीधारकों की कमी नहीं है, लेकिन वे रोजगार नहीं पा रहे हैं. 10वीं परीक्षा में फेल होने वाले 1.05 करोड़ और 12वीं में फेल होने वाले 60 लाख छात्रों के लिए नये रास्ते खोजने होंगे. सरकार को नयी यूनिवर्सिटी बनाने पर जोर देना होगा, जहां छात्रों का कौशल विकास हो सके.

समाज में डिग्रियों का महत्व है, यह बात जानते हुए कि 25 फीसदी इंजीनियर आइटीआइ (कुशल तकनीकी कामगार) के टॉप 25 फीसदी से कम वेतन पाते हैं. कॉलेज को डिग्री प्रदान करने का जरिया बना दिया गया है. कॉलेज का मतलब छात्रों को ऐसी डिग्री प्रदान करने पर होना चाहिए, जो उसे रोजगार मुहैया करा सके. शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए राज्यों को भी ध्यान देना होगा.

राज्यों को अपनी जरूरतों के हिसाब से शिक्षण व्यवस्था बनाने की छूट मिलनी चाहिए. दिल्ली से देश नहीं चल सकता है. प्रधानमंत्री और सभी मुख्यमंत्रियों को मिलकर इस दिशा में काम करना होगा. शिक्षा के अधिकार पर देश की स्कूली व्यवस्था नहीं छोड़ी जा सकती है. देश में शोध के माहौल को बढ़ावा देना होगा. संस्थानों को स्वायत्त बनाना होगा.

उम्मीद है कि इस बजट में शिक्षा को लेकर बड़ी घोषणाएं होगी और सरकार रोजगारपरक शिक्षा व्यवस्था बनाने की दिशा में कदम उठायेगी. संस्थानों के निर्माण के अलावा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराने के लिए केंद्र सरकार कदम उठायेगी. सबसे अधिक कॉलेज होने के बावजूद अगर भारत कुशल कामगार नहीं मुहैया करा पा रहा है, तो यह हमारे शिक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी कमी मानी जा सकती है. अब नीति-निर्माताओं को इस पर गंभीरता से विचार करना होगा तभी देश का आर्थिक विकास दर दहाई अंकों में पहुंच पायेगा और देश से गरीबी दूर हो पायेगी.

*(विनय तिवारी से बातचीत पर आधारित)*

## कुछ आर्थिक शब्दावली

■ **आय कर :** लोगों की व्यक्तिगत आमदनी एक तय सीमा से ज्यादा होने की दशा में सरकार उनसे टैक्स वसूलती है, जिसे आय कर कहा जाता है. वित्तीय वर्ष 2014-15 में ढाई लाख रुपये सालाना की आमदनी पर कोई आय कर देय नहीं है. उसके बाद की आमदनी पर इनकम टैक्स चुकाना होता है.

■ **मानक कटौती :** लोग अपनी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा बीमा, जनरल प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (एनएससी), टैक्स बचाने वाले म्यूचुअल फंड, एफडी आदि में निवेश करते हैं, तो नियमों के मुताबिक उन्हें टैक्स में छूट दी जाती है. जिस सीमा तक यह छूट दी जा सकती है, उसे मानक कटौती कहा जाता है.

■ **सकल घरेलू उत्पाद :** देश की अर्थव्यवस्था के सभी उत्पादक सेक्टरों के उत्पादन का मूल्य सकल घरेलू उत्पाद (ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट) कहलाता है. इसे जीडीपी के नाम से भी जाना जाता है.

■ **राजकोषीय घाटा :** आमदनी और खर्च के गैप को पाटने के लिए सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष लिया जाने वाला अतिरिक्त कर्जा राजकोषीय घाटा कहलाता है. राजकोषीय घाटा घरेलू कर्ज पर बढ़ने वाला अतिरिक्त बोझ माना जाता है.

■ **कर राजस्व :** सरकार अपने खर्च चलाने के लिए लोगों और कंपनियों पर सीधे टैक्स लगाती है. वह लोगों की ओर से इस्तेमाल वस्तुओं और सेवाओं पर भी टैक्स लगाती है. यह सरकार की आय का प्राथमिक और प्रमुख स्रोत है.

■ **गैर कर राजस्व :** प्रत्यक्ष कर (डायरेक्ट टैक्स) और अप्रत्यक्ष कर (इनडायरेक्ट टैक्स) के अलावा सरकार के राजस्व का प्रमुख स्रोत है यह. इसमें सरकार को हासिल होने वाला ब्याज, स्पेक्ट्रम नीलामी से हासिल पैसा और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में सरकारी हिस्सेदारी से हासिल रकम शामिल है.

## नजरिया विशेषज्ञों का

भारत अपने जीडीपी का करीब तीन फीसदी ही शिक्षा पर खर्च करता है, इसलिए इस क्षेत्र में बजट आवंटन जरूर बढ़ना चाहिए. शिक्षा को सुगम और प्रासंगिक बनाने के लिए सरकार को अच्छी नीतियां लानी चाहिए. पश्चिमी देशों की तर्ज पर सरकार द्वारा समर्थित शिक्षा-ऋण की योजनाएं लागू होना जरूरी है. 'मेक इन इंडिया' अभियान की सफलता के लिए बेहतर पाठ्यक्रम, शोध सुविधाएं, पेशेवर और वैज्ञानिक आवश्यक शर्त हैं. मेरी राय में शिक्षा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की फिलहाल कोई संभावना नहीं है, लेकिन हमारी व्यवस्था में विदेशी विश्वविद्यालयों की भागीदारी से शैक्षणिक परिदृश्य में सुधार आयेगा.

**- डॉ रुद्र सेनसर्मा,** *अर्थशास्त्री, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, कोलकाता*

शिक्षा के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर की भारी मांग को सार्वजनिक खर्च से पूरा नहीं किया जा सकता है. इसलिए विदेशी निवेशकों को आकर्षित करना जरूरी है. ऐसी पहल से हमारी संस्थाओं की गुणवत्ता, छात्रों की सीखने की क्षमता, शोध की दिशा, वैश्विक साझेदारी और रोजगार-क्षमता पर सकारात्मक असर पड़ेगा.

**- रोहिन कपूर,** *वरिष्ठ प्रबंधक, डेलॉयट (भारत)*

# बेहतर शिक्षा पर हो सरकार का जोर



पार्थ जे शाह
**प्रेसीडेंट, सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी**

**शिक्षा के अधिकार कानून के तहत निजी स्कूलों में 25 फीसदी सीटें आर्थिक रूप से गरीब बच्चों को दी जानी है. इसके तहत सरकार निजी स्कूलों को मदद मुहैया कराती है. इसे अगर वाउचर सिस्टम के दायरे में लाया जाये, और पैसा या वाउचर सीधे अभिभावकों को दिया जाये, तो वे अपने पसंदीदा स्कूलों में बच्चों को डाल सकते हैं.**

आम बजट को लेकर प्रत्येक क्षेत्र के लोगों को उत्सुकता रहती है. शिक्षा हरेक नागरिक की जरूरत है. इसलिए सरकार की तरफ से शिक्षा मद को प्राथमिकता दी जानी चाहिए. आज तक विभिन्न सरकारों का फोकस यह रहा है कि शिक्षा के लिए जो भी राशि दी जाती है, उसमें संस्थागत ढांचे विशेष रूप से नये स्कूलों के निर्माण, उसके भवन, और भवन के अंदर सुविधाओं को प्राथमिकता दी जाये. पिछली बार के बजट में आइआइटी, आइआइएम जैसे संस्थानों को खोले जाने और स्कूलों में सुविधाओं के विस्तार के लिए प्रावधान किये गये थे. अब सरकार को शिक्षा के गुणवत्ता की दिशा में ध्यान केंद्रित करना चाहिए.

शिक्षा की गुणवत्ता का आकलन सिर्फ एक बार के लिए नहीं बल्कि इस तरह का आकलन हमेशा किया जाना चाहिए. इसके लिए विशेष प्रावधान करना चाहिए. कक्षा तीन, पांच और आठ में सालाना स्तर पर बच्चों ने क्या सीखा और उनको किस तरह की शिक्षा दी जा रही है, इसके आकलन की व्यवस्था पूरे देश में होनी चाहिए. शिक्षा के क्षेत्र में काफी कुछ खर्च होने के बावजूद बच्चों के सीखने के स्तर को लेकर जो समय-समय पर अलग संस्थाओं द्वारा आकलन किया गया और उससे जो तथ्य सामने आये हैं, उसे किसी भी लिहाज से संतोषजनक नहीं कहा जा सकता. शिक्षा का प्रसार दूरदराज के इलाकों में हुआ है. बच्चों का स्कूल में दाखिला भी बढ़ा है, लेकिन बावजूद इसके जिस तरह की गुणवत्तापरक शिक्षा उन्हें मिलनी चाहिए, वह स्थिति नहीं दिखाई देती.

अब तक सरकार का ध्यान स्कूलों को बेहतर बनाने पर रहा है. पर इसे बेहतर बनाने और उनकी देख-रेख में अभिभावकों का भी योगदान है, इस तथ्य को सही तरीके से नहीं समझा गया है. स्कूलों की गतिविधियों में माता-पिता की भागीदारी बढ़ाने की जरूरत है. स्कूल प्रबंधन समिति को ज्यादा विस्तार देने व उसे मजबूत किये जाने की जरूरत है.

### पैरेंटल वाउचर प्रोग्राम

इस बजट में सरकार को पैरेंटल वाउचर प्रोग्राम शुरू करना चाहिए. प्रत्येक वर्ष 10 लाख बच्चों को वाउचर दिया जाना चाहिए. इसके तहत माता-पिता खुद तय करें कि उन्हें अपने बच्चे को किस स्कूल में भेजना है. प्रत्येक साल यदि 10 लाख बच्चों को वाउचर प्रोग्राम से जोड़ा जाता है, तो आगामी 5 वर्षों में 50 लाख बच्चे वाउचर प्रोग्राम के दायरे में आ जायेंगे और इस तरह से बेहतर शिक्षा बच्चों को दी जा सकेगी.

शिक्षा के अधिकार कानून के तहत निजी स्कूलों में 25 फीसदी सीटें आर्थिक रूप से गरीब बच्चों को दी जानी है. इसके तहत सरकार की तरफ से स्कूलों को मदद दी जाती है. इसे अगर वाउचर सिस्टम के दायरे में लाया जाये, और पैसा या वाउचर सीधे अभिभावकों को दिया जाये तो वे अपने मन पसंद के स्कूलों में बच्चों को डाल सकते हैं. आज स्थिति यह है कि निजी स्कूलों में इडब्ल्यूएस (इकॉनोमिकली वीकर सेक्शन) यानी आर्थिक रूप से कमजोर तबकों के तहत आने वाली ज्यादातर सीटें खाली रह जाती हैं.

### स्कॉलरशिप सीधे खाते में

शिक्षा से जुड़ा एक महत्वपूर्ण सवाल स्कॉलरशिप को लेकर भी है. सरकार की तरफ से स्कूलों और कॉलेजों में कई तरह की छात्रवृत्ति छात्रों को दी जाती है. लेकिन यह पैसा स्कूल के प्राचार्य के खाते में पहुंचता है. यदि इस पैसे को छात्रों या माता-पिता के पास डायरेक्ट ट्रांसफर किया जाये, तो इससे कई तरह की समस्या सुलझ जायेगी.

इसके साथ ही इस बजट में यह भी प्रावधान किया जाना चाहिए कि जिन छात्रों को स्कॉलरशिप मिलती है, वे किसी भी पसंदीदा संस्थान में दाखिला ले सकते हैं. अभी केवल सरकारी संस्थानों में पढ़ने पर ही स्कॉलरशिप दी जाती है.

पाकिस्तान में (पंजाब एडुकेशन फाउंडेशन के जरिये) एक अच्छी पहल की गयी है. इसके तहत गरीबों के स्कूल को सहयोग दिया जाता है. इस तरह के प्रयोग को अपने देश में भी शुरू करने से काफी फायदा हो सकता है.

चाइल्ड फ्रेंडली स्कूल की बात अक्सर होती है. यह एक टर्म मात्र है, हमें चाइल्ड सेंट्रिक स्कूल की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए. नीति निर्माताओं का ध्यान इस बात पर होता है कि शिक्षक को क्या सुविधाएं दी जा रही हैं. बच्चों को क्या दिया जा रहा है, इसे भी तवज्जो दिया जाना चाहिए. जिस दिन से यह समझा जायेगा कि हर बच्चा अपने आप में खास है और उसकी व्यक्तिगत देखरेख की जाये, तो इसका फायदा होगा. शिक्षक की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए. शिक्षक को अपने काम के लिए वेतन मिलता है, लेकिन यदि कोई शिक्षक अच्छा काम करता है, तो उसके लिए परफॉरमेंस बोनस जैसे प्रावधानों को लागू किया जाए तो इससे स्थिति में सुधार होगा.

### शिक्षा को नहीं बनाया जाता चुनावी मुद्दा

आम तौर पर चुनावी चर्चा में कभी भी शिक्षा को मुद्दा नहीं बनाया जाता, लेकिन हालिया दिल्ली विधानसभा चुनाव में 'आम आदमी पार्टी' की ओर से यह कहा गया कि स्कूलों की गुणवत्ता को इस स्तर तक सुधारेंगे कि सरकारी स्कूल निजी स्कूलों की तरह हो जायें. दूसरी बात भाजपा की तरफ से किरण बेदी ने भी उठाया था कि सरकारी विद्यालयों या कॉलेजों में स्कूल टाइम के अलावा अन्य निजी संस्थानों को वोकेशनल ट्रेनिंग संस्थान चलाये जाने की इजाजत दी जायेगी. यदि सरकार पूरे देश में शहरों, कस्बों और ग्रामीण इलाकों में भी इस तरह की संस्थागत पहल करती है, तो इससे देश में बच्चों को आसानी से वोकेशनल शिक्षा दिये जाने की दिशा में कदम बढ़ाया जा सकता है. ऐसा होने से बिना संस्थागत ढांचे के विस्तार पर अतिरिक्त खर्च किये शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारा जा सकता है.

इसलिए सरकार शिक्षा पर कितना पैसा खर्च करे यह सवाल आज उतना महत्वपूर्ण नहीं है, जितना यह महत्वपूर्ण है कि सरकार के द्वारा दी जाने वाली राशि को कितने बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, ताकि गुणवत्ता बढ़ायी जा सके.

*(संतोष कुमार सिंह से बातचीत पर आधारित)*

■ कैसा लगा यह पेज? अपनी प्रतिक्रिया एवं सुझाव हमें इ-मेल करें : delhi@prabhatkhabar.in ■ आप पत्र भी लिख सकते हैं. हमारा नया पता है- नॉलेज डेस्क, प्रभात खबर दैनिक, 801, केएम ट्रेड टावर, एच-3, सेक्टर 14, कौशांबी, गाजियाबाद- 201010

# अगर जेल में हैं, तो सुरंग बनाने में जुटें!

सक्सेस सीढ़ी...
**दक्षा वैदकर**

दोस्तों, आपने ऐसी फिल्म जरूर देखी होगी, जिसमें हीरो जेल से भागने के लिए सुरंग बनाता है और आखिरकार उस जेल से फरार हो जाता है. हमें यह सब देखने में बड़ा मजा आता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हीरो बेगुनाह है. हीरो का भी हक है कि वह खुश रहे, परिवार के साथ रहे, हीरोइन के साथ डांस करे. दोस्तों जिस तरह हीरो का जेल से सुरंग बना कर निकलना बहुत जरूरी था, उसी तरह आपका भी निकलना जरूरी है. आपको इस काल्पनिक जेल के कैद से निकलना है. एक ऐसी जेल, जिसमें जाने से पहले आपको पता भी नहीं था कि यह एक जेल है. यह जेल आपकी जॉब, बिजनेस कुछ भी हो सकता है. ऐसी परिस्थिति हो सकती है, जिसमें रहना आपको बिल्कुल पसंद नहीं है. तो देर किस बात की है, बस सुरंग बनाइये और इस जेल से बाहर निकलने का रास्ता तलाशिये. आप उस काम को बिल्कुल मत करिये, जिसे आप पसंद नहीं करते. इस परिस्थिति को मत स्वीकारिये. अपनी सुरंग बनाना शुरू कीजिए. अपनी पसंद का काम करना शुरू करिये. अगर नहीं पता कि वह क्या है, तो उसे तलाशिये.

उस फिल्म को याद कीजिये. आप पायेंगे कि जेल में बहुत सारे कैदी थे, लेकिन केवल हीरो ही सुरंग बना पाता है. सवाल उठता है, क्यों? जवाब है- क्योंकि उसके सामने एक लक्ष्य होता है. यह लक्ष्य उसे सुरंग बनाने की प्रेरणा देता है. अब आप अपना लक्ष्य तलाशिये. अगर आपको लगता है कि आप किसी जेल में बंद हैं, तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि यहां से निकल कर आप क्या करना चाहते हैं. आप किस चीज को लेकर बहुत पागल हैं. दूसरी जरूरी बात. सुरंग बनाने के लिए आपको औजारों की जरूरत पड़ेगी. वे औजार हैं आपकी दक्षता और ज्ञान. आप जो करना चाहते हैं, उससे जुड़ी सारी जानकारियां निकाल लें. उसके बाद औजार का प्रयोग धीरे-धीरे शुरू करें. याद रखें, हीरो सुरंग कब बनाता है? दिन में तो वह सभी के साथ काम करता है, लेकिन रात में चुपके से अपनी सुरंग बनाने में लग जाता है. आपको भी यही करना होगा. जब सब आराम से सो रहे होंगे, आपको मेहनत करनी होगी.

daksha.vaidkar@prabhatkhabar.in

### बात पते की...

- अगर आप दुनिया से आगे निकलना चाहते हैं, तो आपको रात को जाग कर भी काम करना होगा, फेसबुक, घूमना, मूवी का त्याग करना होगा.
- जब आप लगातार त्याग करते हैं और सुरंग बनाने में लगे रहते हैं, तो आप पाते हैं कि एक दिन आप जेल से बाहर आ गये हैं. आजाद हैं, खुश हैं.

फॉलो करें... फेसबुक पर www.facebook.com/successsidhi
ट्वीटर पर www.twitter.com/successsidhi

## राशिफल

डॉ सुनील बर्मन (9431108333)

**मेष** (aries)
दिनचर्या स्फूर्त व्यतीत होगी. अपने व्यस्त कार्यक्रम के बीच आप उनके लिए भी समय निकालें, जो आपसे रोमांटिक उम्मीद लगाये बैठे हैं.

**वृष** (taurus)
बाहरी स्थानों के संबंध आपको चोट पहुंचा सकते हैं. आर्थिक प्रबंधन पर नियंत्रण रखें बाकी बकाया निपट जायेंगे. हनुमान चालीसा का पाठ करें.

**मिथुन** (gemini)
पिता द्वारा लाभ प्राप्त होगा. कोई ऊंची पहुंचवाले व्यक्ति से लाभ मिल सकता है. नौकरीपेशा वाले व्यक्ति को उन्नति की संभावना है.

**कर्क** (cancer)
संभव हो तो थोड़ा कहीं बाहर भ्रमण कर आवें मन में ताजगी आयेगी. वाहन आदि थोड़ी सावधानी से चलावें. बजरंबली के मंदिर में लड्डू चढ़ावें.

**सिंह** (leo)
थोड़ी विशेष मेहनत आपको सफलता प्रदान करायेगी. थोड़ा योग ध्यान करें फिर इसका लाभ आप दिल दिमाग दोनों ओर उठा सकते हैं.

**कन्या** (virgo)
विवेकपूर्ण निर्णय आपको रुके हुए कार्य को संपादित करायेगा. थोड़े और प्रयास आपके पैतृक संपत्ति के प्राप्ति में सहायक होगा.

**तुला** (libra)
ओम रां राहवे नमः और ओम हं हनुमते नमः के जाप से ही दिनचर्या का शुभारंभ करें हो सके तो आज कोई बाहरी यात्रा का कार्यक्रम न बनायें.

**वृश्चिक** (scorpio)
थोड़ी जोर जबरदस्ती से बकाये रकम की प्राप्ति हो सकती है. अपने खानपान व क्रियाकलाप को अनुशासित ढंग से चलने दें. दरिद्रनारायण को भोजन करायें.

**धनु** (sagittarius)
बुद्धिदाता श्रीगणेश जी की पूजा करके घर से निकलें क्योंकि आपके सुबुद्धिपूर्ण निर्णय से कोई बड़ा कार्य संपन्न होने जा रहा है.

**मकर** (capricorn)
कर्म क्षेत्र में विशेष सम्मान की प्राप्ति होगी. थोड़ी कठिनाइयों के बाद मकान-जमीन संबंधी कार्य में सफलता मिल सकती है.

**कुंभ** (aquarius)
पुरुषार्थ करने से ना चुकें, सफलता आपकी प्रतीक्षा कर रहा है. पराक्रम बल से किये गये कर्मों का लाभ मिलेगा. हनुमान जी को ध्यावें.

**मीन** (pisces)
सट्टे-लॉटरी के माध्यम से लाभ प्राप्ति के योग बनते हैं. आयुष्य लाभ मिलेगा. कुटुंब के सहयोग से सामाजिक कार्य बनेंगे. देवगुरु वृहस्पति को स्मरण करें.

## सुडोकू नवताल क्र. 2834

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2 | 4 | 5 | 6 | | 3 |
| | 2 | | 1 | | | | 4 | |
| 5 | 4 | 1 | | 9 | | | | 7 |
| 7 | | | | | | 1 | | 8 |
| 4 | | 8 | 7 | 3 | 6 | 9 | | 2 |
| 9 | | 3 | | | | | | 4 |
| 6 | | | | 8 | | 2 | 7 | 5 |
| | 9 | | | | 4 | | 8 | |
| 1 | | 5 | 3 | 2 | 7 | | | |

MANGAL SENCHA, BANGALORE

सूडोकू नवताल-2833

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 6 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 7 |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 9 | 5 | 6 | 8 |
| 1 | 5 | 7 | 2 | 8 | 6 | 4 | 9 | 3 |
| 5 | 7 | 8 | 6 | 2 | 1 | 9 | 3 | 4 |
| 3 | 2 | 1 | 7 | 9 | 4 | 8 | 5 | 6 |
| 6 | 4 | 9 | 8 | 5 | 3 | 2 | 7 | 1 |
| 2 | 6 | 4 | 5 | 1 | 7 | 3 | 8 | 9 |
| 7 | 1 | 5 | 9 | 3 | 8 | 6 | 4 | 2 |
| 9 | 8 | 3 | 4 | 6 | 2 | 7 | 1 | 5 |

- प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक हैं. इनका क्रमवार होना आवश्यक नहीं है.
- आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3×3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें.
- पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते. पहेली का केवल एक ही हल है.